

Regarding merger of government schools in Uttar Pradesh- laid

श्री आदित्य यादव (बदायूं) : उ०प्र० में परिषदीय विद्यालयों को मर्जर के नाम पर बंद किया जा रहा है। वैसे भी परिषदीय विद्यालयों में गरीब तबके के बच्चे शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। वह भी सरकार द्वारा अब यह कह कर बंद किया जा रहा है कि जिस परिषदीय विद्यालय में 50 बच्चे से कम होंगे उस विद्यालय को किसी अन्य विद्यालय में मर्जर किया जाएगा। मैं यह भी अवगत कराना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा जिलाधिकारी से मर्जर किये जाने स्कूलों की सूचना चाही गयी किन्तु सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई। जो भी परिषदीय विद्यालय बंद करके उसे किसी अन्य विद्यालय में मर्जर किया जा रहा है उसकी दूरी अधिक होने के कारण छोटे-छोटे बच्चे विद्यालय नहीं पहुंच पाएँगे तथा शिक्षा से वंचित रह जाएँगे। जहाँ सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, यह कैसा साथ तथा विकास है कि उ०प्र० में गरीब के बच्चों को शिक्षा से वंचित कर दिया जाए। आज हम विश्व गुरू बनने की बात कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ हम गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित कर रहे हैं। मैं जापान की बात बताता हूँ जहाँ जापान के होकाईदो द्वीप के कामी शिराताकि गाँव में एक बच्ची को स्कूल ले जाने तथा वापस लाने के लिए एक ट्रेन चलाई जाती है यह ट्रेन विशेष रूप से उस बच्ची के लिए है और उसके अलावा कोई और इस पर सवार नहीं होता है। ट्रेन का समय भी बच्ची के स्कूल के समय के अनुसार समायोजित किया गया है। प्राइमरी स्कूलों को मर्जर किये जाने से वहाँ के शिक्षक, शिक्षामित्र तथा रसोइयें बेरोजगार हो जाएँगे। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह इस मामले को संज्ञान में लेते हुए उ०प्र० सरकार को दिशानिर्देशित करते हुए परिषदीय स्कूलों में बच्चों की कमी के नाम पर मर्जर करने से रोके जाने की कृपा करें।